नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 035
दि. 04.06.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'पाताल में भी छुप जाओगे तो ढूंढ निकालेंगे...' गोरखपुर में सहएू योगी की अपराधियों को वार्निंग

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गीडा के विकास कार्यों के लोकार्पण और संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2026 के दौरान अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का सुरक्षा मॉडल अब मिसाल बन चुका है. कानून से खिलवाड़ करने वालों को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर पहुंचे. उन्होंने गीडा (ऋऋऊअ) क्षेत्र के

फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवासों के लोकार्पण-शिलान्यास और संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2026 का शुभारंभ किया. इस अवसर पर सुरक्षा और सुशासन को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि हमने 2017 में सरकार बनते ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करके राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उद्यम और समृद्धि के लिए सुरक्षा सबसे पहली शर्त है, जिसे सरकार बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को उपलब्ध करा रही है और युवाओं के रोजगार पर डकैती डालने वालों से सख्ती से निपट रही है.

अपराधियों को पाताल से भी खोज निकालेगी सरकार

सीएम योगी ने कड़े लहजे में कहा कि सरकार सबका विकास करेगी और योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को देगी. लेकिन, अगर किसी ने 'मनबढ़ई' करके गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, व्यापारी को धमकाया या बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, तो सरकार उसे कतई नहीं छोड़ेगी. ऐसे अपराधी चाहे पाताल में भी क्यों न छुप जाएं, उन्हें वहां से भी खोजकर निकाल लिया जाएगा.

गीडा में 50 हजार युवाओं को मिला रोजगार

मुख्यमंत्री ने यूपी के सुरक्षा मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि अनुकूल माहौल की वजह से ही आज लाखों नौजवानों को काम मिल रहा है. अकेले गीडा में लगे उद्योगों के माध्यम से 50 हजार युवाओं को नौकरी और कार्य मिला है. इस औद्योगिक क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के साथ-साथ देश के अलग-अलग कोनों से आए युवा बिना किसी डर के काम कर रहे हैं, जो बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही संभव हो सका है.

2017 की पहली कैबिनेट से ही किसानों को बड़ी राहत

खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार की पहली कैबिनेट में ही कर्ज से दबे किसानों को कर्ज मुक्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था. उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार अन्नदाता किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने के लिए जगह-जगह सरकारी क्रय केंद्र खोलकर उपज खरीदने की प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिससे किसानों को सीधा लाभ हुआ.

लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किया पूरा

मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि दशकों से प्रदेश में लंबित पड़ी बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना और बुंदेलखंड की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को उनकी सरकार ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया. इन प्रयासों के चलते राज्य की 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है,।

गीडा बना रोजगार का नया हब, सीएम योगी ने 208 करोड़ की 71 परियोजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार (3 जून) को गोरखपुर के गीडा सेक्टर-13 में 208 करोड़ रुपये की लागत से तैयार फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स और ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवासीय परिसर समेत 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, रोजगार, उद्योग और विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया और कहा कि सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गीडा में जितने उद्योग लगे हैं, उनसे 50 हजार नौजवानों को रोजगार और काम मिला है. इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवा काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा का माहौल नहीं होता तो यह संभव नहीं हो पाता.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि विकास भी होगा और योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलेगा. साथ ही सुरक्षा की भी पूरी गारंटी दी जाएगी. उन्होंने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई गरीब का हक छीनने, व्यापारी को धमकाने या बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो सरकार उसे छोड़ेगी नहीं. उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी पाताल में भी छिप जाएगा तो उसे खोजकर बाहर निकाल लिया जाएगा. भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी इसी तरह सख्ती से कार्रवाई की जा रही है.

प्रधानमंत्री ने दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग की घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आगजनी की घटना को दुखद बताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग में हुई जानमाल की हानि बेहद दुखद है। अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगेः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पीओके : 'चुनाव से पहले दखल दें प्रधानमंत्री', PoK के नेता ने PM Modi से मांगी मदद, बताई अंदर की बात

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और गिलगित-बाल्टिस्तान से एक बार फिर मानवाधिकारों को लेकर

गंभीर सवाल उठे हैं। PoK के मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकताओं और आम नागरिकों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है और विरोध की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। बता दें कि PoK में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं।

छठी बार भारत आ रहीं डेल्सी रोड्रिगेज; क्यों बेहद खास है वेनेजुएला की एक्टिंग प्रसीडेंट का यह दौरा

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि डेल्सी रोड्रिगेज एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ रही हैं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना तथा परिवहन मंत्रालयों के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज 3 जून बुधवार शाम भारत पहुंचेंगी। उनका यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, रोड्रिगेज भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी और इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने पर चर्चा होगी।

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि डेल्सी रोड्रिगेज एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आ रही हैं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना तथा परिवहन मंत्रालयों के वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। इस बीच क्या रहेगा उनका शेड्यूल आइए जानते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और एस. जयशंकर से होगी मुलाकात

दौरे के दौरान रोड्रिगेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगी। इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ भविष्य के सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने डीके शिवकुमार, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

(जीएनएस)।

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार संभालने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा भी जताया।

प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ह्लडीके शिवकुमार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं ह्व उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक की जनता के कल्याण और राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी।

राजनाथ सिंह ने भी दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट कर शिवकुमार को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी ओर से मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं हैं।

बेंगलुरु में हुआ शपथ ग्रहण समारोह

इससे पहले बुधवार को डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु स्थित लोक भवन परिसर के ग्लास हाउस में आयोजित समारोह में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। थावरचंद गहलोत ने शाम 4:10 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

आध्यात्मिक गुरु को किया नमन

समर्थकों के नारों के बीच शिवकुमार मंच तक पहुंचे और आध्यात्मिक संत वीर गंगाधर स्वामीजी, जिन्हें अज्जय्या या नोनाविनाकेरे अज्जा के नाम से भी जाना जाता है, के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। संविधान की प्रति हाथ में लेकर शपथ लेते समय शिवकुमार ने अपने आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले वीर गंगाधर अज्जा का स्मरण भी किया।

कांग्रेस के शीर्ष नेता रहे मौजूद

शपथ ग्रहण समारोह की शुरूआत 'वंदे मातरम्' से हुई, जिसके बाद कर्नाटक राज्य पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राज्य गीत भी बजाया गया। समारोह में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

13 मंत्रियों ने भी ली शपथ

डीके शिवकुमार के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली और नई कर्नाटक सरकार ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। दलित समुदाय के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री जी परमेश्वर ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल गठन के पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के पुत्र और कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्दारमैया तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति ने 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में भाग।

लद्दाख में नए अवसरों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लेख को पीएम मोदी ने साझा किया

लद्दाख में नए अवसरों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लेख को पीएम मोदी ने साझा किया, पीएम नरेन्द्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। श्री मोदी ने लेख को ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि देश वैश्विक स्तर पर 'वोकल टू लोकल' की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

'क्या आप अपनी चुप्पी तोड़ेंगे?', अमेरिका में तिरंगे के अपमान पर संजय सिंह का पीएम मोदी से सवाल

अमेरिका में भारतीय तिरंगे के अपमान का वीडियो शेयर कर अअढ सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अमेरिका में भारतीय तिरंगे के अपमान का वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट कर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए।

संजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मोदी जी, आपके फ्रेंड ट्रंप के देश अमेरिका में भारत की शान 'तिरंगा झंडा' फाड़ा जा रहा है। क्या आप इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे?' उन्होंने कहा कि कभी ट्रंप भारत को नरक बोलता है और कभी

उनके देश में भारतीय तिरंगे का अपमान होता है।

AAP सांसद ने आगे लिखा, 'आप कब बोलोगे? ट्रंप के लिए पूजा करने वाले अंधभक्तों, तुम भी देखो।' इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें तिरंगे के अपमान का वीडियो दिखाया गया है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

वीडियो देखकर भड़के यूजर्स

संजय सिंह के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों के समर्थक जहां केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा समर्थक इस मामले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स का पारा हाई है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर अधिकांश यूजर्स ने लिखा है कि 'हमारे ध्वज को अमेरिका में फाड़ा जा रहा है यह देख कर खून खौलता है सच्चे भारतीयों का।'

ममता बनर्जी को बड़ा झटका, बागी विधायक ऋतुब्रत बनर्जी बने TMC विधायक दल के नेता

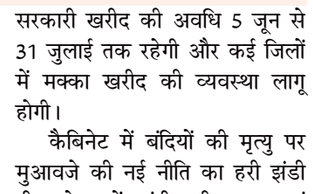

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज फिर बड़ा धमाका हो गया है। टीएमसी के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सड़क पर आ गई है। निष्कासित नेता ऋतुब्रत बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि उन्हें प्रतिपक्ष TMC विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। इस बयान के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में हलचल और तेज हो गई है। ऋतुब्रत बनर्जी ने ये ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस ने उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, बढ़ाया गया सरकारी वकीलों का भत्ता

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को उनके सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में 24

प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकारी वकीलों के भत्ते में बढ़ोतरी के

साथ मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया और लाखों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी गई है।

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति के साथ ही कारागार विभाग, सिंचाई विभाग, आबकारी विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कृषि व स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्ताव को दी हरी झंडी दी है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 प्रति कुंतल तय किया गया। मक्का की सरकारी खरीद की अवधि 5 जून से 31 जुलाई तक रहेगी और कई जिलों में मक्का खरीद की व्यवस्था लागू होगी।

कैबिनेट में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजे की नई नीति का हरी झंडी दी। जेल में बंदी की मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति को मंजूरी दी गई है।

18 शहरों में GCC मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और बड़े शहरों में अउ इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्ते बढ़ाए गए, मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन मंजूर की गई और पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को मंजूरी मिली है।

पीएम मोदी की अपील का असर: सीएम मोहन के काफिले में पहली बार इलेक्ट्रिक कार शामिल, ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ाए कदम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के काफिले में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत अपील से प्रेरित है।

(जीएनएस)।

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने की अपील का असर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के काफिले में भी दिखाई देने लगा है।

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक काफिले में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए महिंद्रा की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक एसयूवी एक्स 9ी खरीदी गई है, जो बुधवार से मुख्यमंत्री के काफिले का हिस्सा बन गई है।

मुख्यमंत्री बुधवार शाम दिल्ली रवाना होते समय मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक इसी इलेक्ट्रिक कार में सफर करेंगे। महिंद्रा के अनुसार यह वाहन एक बार चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है।

काफिला छोटा हुआ, डीजल की खपत घटी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने की पहल की थी। इसका सीधा

असर ईंधन खपत पर दिखाई दिया है। गैरेज सूत्रों के अनुसार अप्रैल 2026 में जहां वीआईपी वाहनों में लगभग 24 हजार लीटर डीजल की खपत हुई थी, वहीं मई में यह घटकर 18 हजार लीटर रह गई। यानी एक माह में करीब 6 हजार लीटर डीजल की बचत दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 7 कर चुके हैं। उनकी इस पहल के बाद कई मंत्रियों और अधिकारियों ने भी कार-पूलिंग तथा कम वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

मुख्यमंत्री की नई इलेक्ट्रिक कार को विशेष नंबर टढ 02 श्इ 2047 आवंटित किया गया है। इसमें 'श्इ' का अर्थ 'विकसित भारत' और '2047' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प वर्ष को दशार्ता है। इस नंबर के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का संदेश देने की कोशिश की गई है।

पहली बार काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन

मुख्यमंत्री के आधिकारिक काफिले में पहली बार किसी इलेक्ट्रिक कार को शामिल किया गया है। इसे सरकारी परिवहन व्यवस्था में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए वाहन की तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है। ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने भी आवश्यक परीक्षण कर लिए हैं।

आधुनिक सुविधाओं से लैस है एक्स 9ी

महिंद्रा एक्स 9ी को कंपनी की सबसे आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों में गिना जाता है। इसमें 360 डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, फास्ट चार्जिंग तकनीक, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वाहन लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उपयुक्त माना जा रहा है।

सीएम योगी ने की रवि किशन की तारीफ, बोले- 'फिल्म भले फ्री में न दिखाएं, लेकिन हर कार्यक्रम में रहते हैं मौजूद'

गोरखपुर में ₹208 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन की जमकर तारीफ की।

(जीएनएस)।

गोरखपुरः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में ₹208 करोड़ की लागत से तैयार विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, ईडब्ल्यूएस (एहर) और एलआईजी (छक्क्ष्) आवासीय परिसर समेत कई विकास योजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित किए और ठक्एछक्ळ कौशल केंद्र से प्रशिक्षित छात्रों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन भी मौजूद रहे, जिनकी मुख्यमंत्री ने मंच से तारीफ करते हुए सराहना की।

करोड़ों की परियोजनाओं की दी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गीडा क्षेत्र में विकसित की जा रही परियोजनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देंगी। उन्होंने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को प्रदेश के औद्योगिक

विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अत्याधुनिक फ्लैटेड फैक्ट्री में एक ही परिसर के भीतर एमएसएमई क्षेत्र के 100 से अधिक उद्योग संचालित हो सकेंगे। यह मॉडल न केवल प्रदेश बल्कि देश और वैश्विक स्तर पर भी औद्योगिक विकास का अनुकरणीय उदाहरण बनेगा।

लाभार्थियों और छात्रों को सौंपे प्रमाण-पत्र

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एहर और छक्क्ष् आवासीय योजनाओं के लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित किए। इसके अलावा औद्योगिक भूखंड आवंटियों को भी दस्तावेज सौंपे गए। ठक्एछक्ळ कौशल केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाण-पत्र देकर मुख्यमंत्री ने उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

मंच से रवि किशन की तारीफ

कार्यक्रम में सांसद रवि किशन की मौजूदगी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हल्के-फुल्के अंदाज में उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, "भले ही आपको ये फ्री में फिल्म न दिखाते हों, लेकिन सभी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। योजनाओं में सक्रिय भागीदारी दिखाते हैं।" मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर प्रतिक्रिया दी।

'काम करने का जज्बा है रवि किशन में'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि रवि किशन उनसे कह रहे थे कि यदि मैं कहूं तो वह इस भीषण गर्मी में नंगे पैर पदयात्रा भी निकाल सकते हैं। इस पर सीएम ने जवाब दिया कि पहले बारिश हो जाने दें, उसके बाद इस बारे में विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रवि किशन में काम करने का विशेष जज्बा है और वह एक सांसद के रूप में अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करना जानते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मंच पर इतनी गर्मी होने के बावजूद रवि किशन लगातार भाषण दिए जा रहे हैं।

औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्वांचल को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। गीडा में विकसित हो रही नई परियोजनाएं निवेश, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इन योजनाओं से क्षेत्र के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? तारीख बताए चुनाव आयोग... हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से भी मांगा जवाब

(जीएनएस)।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्वाचन आयोग से पूछा है कि वह तारीख बताये की कब होंगे. साथ राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर भी स्पष्टीकरण देने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार 10 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट पेश करे.

(जीएनएस)।

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से पूछा है कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे, सरकार तारीख बताये. ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने और उन्हें प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से तारीख बताने का आदेश दिया है. साथ ही राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर भी स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

दरअसल, राज्य सरकार के उस आदेश के खिलाफ लखनऊ बेंच में

याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाते हुए प्रशासक नियुक्त किया गया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव कब होंगे, तारीख बताई जाए. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार 10 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करे.

ग्राम प्रधानों के कार्यकाल बढ़ने पर कोर्ट सख्त

मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. कोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव को देखते हुए बनाए गए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अगली सुनवाई पर 10 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. स्थानीय अधिवक्ता की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया. याची ने सरकार के इस आदेश को कानून की मंशा के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी है.

प्रदेश में वर्तमान ग्राम प्रधानों को पंचायत चुनाव होने और नए प्रधान चुने जाने तक प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के 25 मई के आदेश को चुनौती दी गई है. जिस पर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका के मुताबिक, यूपी पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रधानों का कार्यकाल उनके शपथ लेने से केवल 5 साल का ही हो सकता है. लेकिन सरकार ने समय पर पंचायत चुनाव न करा कर मौजूद प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया है. ऐसा करके एक प्रकार से उनका कार्यकाल अनिश्चितकाल तक बढ़ा दिया है, जो विधि विरुद्ध है. याचिका में मांग की गई कि पहले यदि पंचायत चुनाव नहीं हो पाते थे तो एडीओ पंचायत या किसी अन्य अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता था. उसी प्रकार इस बार भी होना चाहिए था.

सीएम ने जनता दर्शन में, भूमि संबंधी प्रकरणों में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में भूमि संबंधी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

(जीएनएस)।

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में भूमि संबंधी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकरण की गंभीरता के अनुसार संबंधित के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीएम को कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कुछ लोगों ने जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व कर्मियों की तरफ से लापरवाही किए जाने की शिकायत की तो उन्होंने डीएम को तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने कहा कि सरकार इलाज में पूरी मदद करेगी। इसके लिए जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा और

इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े।

सीएम योगी ने 150 लोगों से की मुलाकात

जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है।

वहीं, एक महिला ने कुछ लोगों द्वारा मकान से बेदखल किए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि मकान पर महिला का कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने अलग-अलग मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए।

जरूरतमंद लोगों का जल्द बनवाए जाए आयुष्मान कार्ड-सीएम योगी

जनता दर्शन में एक महिला ने मां के इलाज के लिए सहायता देने का निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। इस पर सीएम ने मौके पर मौजूद अफसरों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए, अधिकारी हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनवाएं, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि उन्हें विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सीएम योगी ने की गोसेवा

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। सुबह गुरु गोरखनाथ और अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर की गोशाला में गोसेवा की। गोवंश को अपने हाथ से गुड़-रोटी खिलाकर उन पर स्नेह बरसाया।

बच्चों को दी चॉकलेट

इसी क्रम में मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए उन्होंने परिजनों के साथ आए बच्चों को पास बुलाकर उन्हें चॉकलेट दीं और उनसे पढ़ाई के बारे में बातचीत की। सीएम ने बच्चों को खूब पढ़ने-आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया।

लखनऊः भाजपा नेता की हत्या मामले में CCTV से मिले अहम सुराग, चार आरोपियों की तलाश में पुलिस

लखनऊ के विभूतिखंड स्थित जलवा क्लब के बाहर भाजपा नेता शिवम सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने चार और संदिग्ध आरोपियों की पहचान की है।

(जीएनएस)।

लखनऊ। विभूतिखंड स्थित जलवा क्लब के बाहर भाजपा नेता शिवम सिंह की हत्या के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है।

अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने चार और संदिग्ध आरोपियों को चिह्नित किया है। सीसी फुटेज और गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर इनकी पहचान की गई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

विभूतिखंड पुलिस के अनुसार, हत्याकांड के मुख्य आरोपित और 25 हजार रुपये के इनामी अनुज सिंह को चंदौली के मुगलसराय क्षेत्र से गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ था। इसके अलावा विभूतिखंड पुलिस

इस मामले में अलीगंज निवासी शांतनु उर्फ अंकित रावत, हनी तिवारी उर्फ विवेक तथा आजमगढ़ निवासी विवेक सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

जांच के दौरान पुलिस ने जलवा क्लब और उसके आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में सामने आया कि घटना के समय गिरफ्तार आरोपितों के अलावा कुछ अन्य युवक भी मौके पर मौजूद थे।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ और फुटेज के आधार पर चार अन्य संदिग्धों की पहचान कर ली है। उनकी तलाश में तीन विशेष टीमें लगाई गई हैं। अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र के रामनगर धौरहरा निवासी शिवम सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कमेटी के सदस्य थे।

वह 25 मई की रात अपने दोस्तों निलेश, जीशान और एक अन्य साथी के साथ विभूतिखंड स्थित जलवा क्लब में पार्टी करने आए थे। 26 मई की सुबह करीब तीन बजे क्लब से बाहर निकलने के दौरान सिगरेट पीने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी विवाद में हमलावरों ने ईंट-पत्थरों से हमला कर शिवम की हत्या कर दी थी। हाईप्रोफाइल हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक नाराजगी जताई गई थी।

इसके बाद एसीपी विभूतिखंड विनय द्विवेदी, तत्कालीन इंस्पेक्टर अमर सिंह समेत दो उपनिरीक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया था। डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि मामले में कुछ और लोगों की पहचान की गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सहारा शहर लीज रद मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और लखनऊ नगर निगम को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा शहर की लीज रद्द कर कब्जा लेने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ नगर निगम से जवाब तलब किया है।

(जीएनएस)।

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा शहर की लीज रद कर के उसका

कब्जा लेने के मामले में राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को करने को कहा है।

गौरतलब है कि सहारा शहर की जमीन का कब्जा वापस लेने के बाद राज्य सरकार वहां पर नई विधानसभा बनाने पर विचार कर रही है। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची एवं जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने मेसर्स सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन की ओर से दाखिल एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए गत 29 मई को पारित किया।

मामले की सुनवाई के बाद पीठ ने राज्य सरकार, लखनऊ नगर निगम, नगर आयुक्त एवं नगर निगम के प्रभारी अधिकारी संपत्ति को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस पर कोर्ट में उक्त विपक्षीगणों की ओर से पेश हो रहे अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त कर ली, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार, नगर निगम सहित सभी विपक्षीगणों को मामले में 31 जुलाई तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

सहारा ने एसएलपी दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के गत 22 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने सहारा की लीज डीड खारिज होने व उसका कब्जा लेने के नगर निगम के आदेशों के खिलाफ याचिका को सुनवाई योग्य न होने के आधार पर खारिज दिया था और कहा कि चूंकि सहारा सेबी विवाद में यह विवाद भी शामिल है, लिहाजा उसके हाथ बंधे हैं और मामले को सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है।

दरअसल, सहारा ने नगर निगम के आठ सितंबर, 2025 को जारी एक आदेश को चुनौती दी थी जिससे उसने सहारा को 22 अक्टूबर 1994 को दी गई जमीन की लीज को खारिज कर दिया था और 11 सितंबर, 2025 को एक और आदेश जारी करके उक्त जमीन को खाली कराने का आदेश भी कर दिया था।

सहारा की ओर से तर्क दिया गया था कि दो सितंबर, 2017 को एक आर्बिट्रेशन मामले में इसी जमीन को लेकर उसके हक में आदेश पारित हो चुका था किंतु नगर निगम ने उस आदेश की अनदेखी करके गलत तरीके से पट्टे को खारिज किया था जबकि वह उसका समय बढ़ाने के लिए आवश्यक पैसा जमा करने को तैयार था।

भारत से नेपाल ले जा सकेंगे 5 गुना ज्यादा सामान, टैक्स फ्री

(जीएनएस)।

नेपाल सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सड़क मार्ग से सीमा पार करने वाले लोगों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। पिछले नियम के कारण सीमा इलाकों में रहने वाले लोगों, छोटे व्यापारियों और रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी।

कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और मामला नेपाल संसद तक पहुंच गया था। लगातार बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने नियम में बदलाव किया है। नए फैसले को सीमा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

क्या बदला है नया नियम?

नेपाल के वित्त मंत्रालय ने राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि अब सड़क मार्ग से सीमा पार करने वाले यात्री 500 रुपये तक के निजी इस्तेमाल के सामान को बिना कस्टम ड्यूटी के ला और ले जा सकेंगे। इससे पहले यह सीमा सिर्फ 100 रुपये थी। नए नियम के तहत कस्टम अधिकारी सामान की जरूरत और उपयोग को देखकर उसे ड्यूटी-फ्री अनुमति दे सकते हैं। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सीमित मूल्य के निजी सामान पर लागू होगी और बड़े कमर्शियल सामान पर नहीं।

पुराने नियम पर क्यों हुआ था विरोध?

मई 2025 में नेपाल सरकार ने 100 रुपये से ज्यादा कीमत का सामान बिना टैक्स लाने पर रोक लगा दी थी। इस नियम का सबसे ज्यादा असर सीमा

क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ा था, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से खरीदारी करते हैं। कई सीमा चौकियों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। व्यापारियों और स्थानीय संगठनों ने कहा था कि 100 रुपये की सीमा व्यावहारिक नहीं है और इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

संसद तक पहुंचा था मामला

सीमा क्षेत्रों में बढ़ते विरोध के बाद यह मुद्दा नेपाल संसद में भी उठा था। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने माना था कि यह नियम पिछली सरकार के समय बनाया गया था और मौजूदा सरकार इसमें बदलाव पर विचार कर रही है। उन्होंने संसद में भरोसा दिलाया था कि सीमा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राहत देने का प्रयास किया जाएगा। अब सरकार ने सीमा बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है, जिसे उसी वादे की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

छात्रों और व्यापारियों को क्या फायदा?

भारत में पढ़ाई कर रहे नेपाली छात्रों के लिए पहले से लागू विशेष सुविधा जारी रहेगी। वे एक टैबलेट या एक कंप्यूटर बिना कस्टम ड्यूटी के नेपाल ला सकते हैं। वहीं सीमा क्षेत्र के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों ने सरकार के नए फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और सीमा बाजारों में कारोबार भी बेहतर होगा। जानकारों के मुताबिक यह फैसला सरकार और जनता के बीच बने तनाव को कम करने में भी मदद कर सकता है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

पारस्परिक रूप से हो भारत-नेपाल सीमा विवाद

भारत ने मंगलवार को नेपाल के साथ सीमा विवाद के समाधान में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार करने से दो टूक मना कर दिया है। असल में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने रविवार को नेपाली संसद में सीमा विवाद के समाधान के लिए चीन और ब्रिटेन की भागीदारी की वकालत की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बालेन्द्र शाह के बिचौलिए की भूमिका पर स्पष्टीकरण देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और नेपाल के बीच किसी भी समस्या का समाधान दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से किया जाएगा। किसी दूसरे और तीसरे देश की कोई भूमिका स्वीकार नहीं कर सकते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे के समाधान हेतु द्विपक्षीय तंत्र का जो गठन हुआ है, उसमें दोनों देशों के बीच 98 प्रतिशत मामलों को चिह्नित किया जा चुका है।

दरअसल नेपाल वूटनीतिक वुटिलता के तहत भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ाना चाहता है और वह बार-बार सीमा विवाद पर भारत के साथ संबंधों की सौदेबाजी करने के लिए अवसर की तलाश कर रहा है। नेपाल जानता है कि भारत, ब्रिटेन और चीन की भूमिका को नेपाल के साथ सीमा विवाद पर कोई महत्व नहीं देगा फिर भी वह वूटनीतिक सनसनी फैलाने को भी अपनी वूटनीतिक सफलता मान रहा है।

सच तो यह है कि नेपाल ने सीमा विवाद का जो पंगा खड़ा किया है वह चीन की ही वूटनीतिक खुराफात है। चीन के इशारे पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लगभग 372 वर्ग किमी के भूभाग को लेकर संसद से विवादित प्रस्ताव पारित कराया जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल है। इसके अलावा बिहार सीमा के पास स्थित सुस्ता क्षेत्र को लेकर भी एक पुराना मतभेद है। यह विवाद दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संधियों और मुख्य रूप से काली नदी के उद्गम स्थल की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण उत्पन्न हुआ है। संयोग की बात तो यह है कि विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह बयान तब जारी किया जब नेपाल के विदेशमंत्री भारत की धरती पर मौजूद थे। भारत चाहता है कि दोनों देश आपस में ही इस विवाद को खत्म कर लें किन्तु नेपाल दबाव बनाने और स्वनिर्मित इस फजी सीमा विवाद का वैश्वीकरण करने के लिए लालयित है। नेपाल इस बात को अच्छी तरह जानता है कि भारत दुनिया के किसी भी देश के दबाव में आने वाला नहीं है किन्तु नेपाल को वह नाराज भी नहीं करना चाहता।

इसीलिए नेपाल के नेतृत्व से बड़ी नरमी के साथ पेश आता है। भारत भी जानता है कि नेपाल को झुकाने के लिए नईं दिल्ली के पास बहुत सारे तरीके हैं किन्तु इससे काठमांडू के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए बातचीत के माध्यम से ही नेपाल को सहमत करने के प्रयास किए जाते हैं किन्तु इसका मतलब यह है कि जब कभी भी नेपाल भारत को कमजोरी के रूप में मानने की गलती करता है तो उसकी गलतफहमी को दूर करना नईं दिल्ली आवश्यक समझता है।

इसी वूटनीति के तहत विदेश मंत्रालय के बयान को जब देखा जाएगा तभी समझ में आएगा कि वूटनीति में शत्रु देश के साथ अलग स्वर का इस्तेमाल किया जाता है जबकि भटके हुए मित्र के साथ विशेष भाषा, भाव और शैली का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की कोशिश है कि नेपाल नाराज भी न हो और अपनी पूर्ववती सरकार की खुराफाती नीति को समझ भी ले जिसने संबंधों की जड़ में दूसरे देश द्वारा उबाला गया पानी डालने की गलती की। लब्बोलुआब यह है कि नेपाल भारत का शत्रु नहीं बल्कि भटका हुआ मित्र है। भारत ने उसे सही सलाह दी है कि जो भी विवाद है उसे बातचीत से हल करेंगे। इधर उधर के देशों से मध्यस्थता करने की गलतफहमी न पालो।

टेढ़े पैरों के साथ पैदा हुए बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 राज्यों में शुरू हुआ खास इलाज

(जीएनएस)।

अदाणी फाउंडेशन और अनुष्का फाउंडेशन ने एक बड़ी पहल करते हुए तीन साल के लिए हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के 10,000 से ज्यादा बच्चों का 'क्लबफुट' (टेढ़े पैर) का इलाज और फॉलो-अप केयर किया जाएगा।

विश्व क्लबफुट दिवस पर शुरू की गई इस मुहिम को नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के सहयोग से जमीन पर उतारा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य नेटवर्क के जरिए बीमारी की जल्द पहचान करना, रेफरल सिस्टम को मजबूत बनाना और इलाज को आसान बनाना है।

इस पार्टनरशिप की औपचारिक शुरूआत उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर से हुई। संस्थाओं के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में क्लबफुट के मामले देश में सबसे ज्यादा हैं, जहां हर साल करीब 6,000 बच्चे इस समस्या के साथ पैदा होते हैं।

क्लबफुट जन्म के समय होने वाली एक समस्या है, जिसमें बच्चे के एक या दोनों पैर अंदर की ओर मुड़े होते हैं। हर 800 में से करीब एक नवजात इस स्थिति से प्रभावित होता है। दुनिया भर में मान्य 'पोंसेटी' (Ponset) पद्धति से इसका प्रभावी इलाज संभव है। हालांकि, समय पर पहचान न हो पाने और इलाज की कमी के कारण आज भी कई बच्चे, खासकर पिछड़े इलाकों के, इससे जूझ रहे हैं।

इस प्रोग्राम के तहत अगले तीन सालों में 61 जिलों के 67 क्लबफुट क्लीनिकों को मदद दी जाएगी। बेहतर नतीजों के लिए यह पहल कम्युनिटी आउटरीच, क्लीनिकल केयर, क्षमता निर्माण और पीड़ित परिवारों को सहायता देने पर फोकस करेगी।

यही नहीं, इस कार्यक्रम का लक्ष्य 51 स्वास्थ्य पेशेवरों को ट्रेनिंग देना और 30,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को जागरूक करना है, ताकि वे क्लबफुट से प्रभावित बच्चों की जल्द पहचान कर उन्हें सही समय पर अस्पताल भेज सकें।

इस साझेदारी पर अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. प्रीति अदाणी ने कहा कि समय पर पहचान और इलाज से क्लबफुट प्रभावित बच्चे आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। इससे वे शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में भी पूरी तरह हिस्सा ले पाएंगे।

अनुष्का फाउंडेशन के संस्थापक दीपक प्रेमनारायण ने कहा कि इस सहयोग से पांच राज्यों में शुरूआती जांच और इलाज के सिस्टम को मजबूती मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक क्वालिटी ट्रीटमेंट पहुंच पाएगा।

भारत में हर साल करीब 33,000 बच्चे क्लबफुट के साथ पैदा होते हैं, जिनमें से लगभग 12,000 बच्चे इन्हीं पांच राज्यों से हैं। संस्थाओं का कहना है कि इस पहल के जरिए वे सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों और बेहतर रेफरल सिस्टम की मदद से देश में क्लबफुट के बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

1996 में स्थापित अदाणी फाउंडेशन स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, जलवायु और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। यह फाउंडेशन 22 राज्यों में काम कर रहा है और हर साल 1.33 करोड़ से ज्यादा लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाता है।

वहीं, अनुष्का फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संस्था है जो पब्लिक हेल्थ पार्टनरशिप के जरिए क्लबफुट को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। वर्तमान में यह संस्था 13 राज्यों के 165 जिलों में इलाज कार्यक्रम चला रही है। अब तक यह 26,000 से ज्यादा बच्चों का इलाज करा चुकी है। संस्था का दावा है कि भारत में क्लबफुट के साथ पैदा होने वाले हर छह में से एक बच्चे का इलाज अनुष्का फाउंडेशन समर्थित क्लीनिक में होता है।

5 ग्राम से 5 किलो तक के आम, लखनऊ के इस बाग में उग रही दुनिया भर की 352 वैरायटी

(जीएनएस)।

लखनऊ के किसान एसी शुक्ला ने अपने बाग में 352 किस्मों के आमों का संग्रह तैयार किया है। यहाँ 5 ग्राम से 5 किलो तक के आम, भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की वैरायटी मौजूद हैं। बाग

में हाई-डेंसिटी प्लांटेशन, ग्राफ़्टिंग तकनीक, सालभर फल देने वाली किस्में और जैविक प्रबंधन जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। शुक्ला का मानना है कि बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में आम की खेती को नई किस्मों और नए प्रबंधन तरीकों की जरूरत है।

आम के बागों में दशहरी, लंगड़ा या चौसा जैसे कुछ चुनिंदा नाम आमतौर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन लखनऊ के किसान एसी शुक्ला का बाग इस मायने में अलग है कि यहाँ आम सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एक संग्रहालय की तरह दिखाई देता है। इस बाग में 352 किस्मों के आम मौजूद हैं, जिनमें 5 ग्राम के अंगूर दाना आम से लेकर 5 किलो वजन वाले गजानन आम तक शामिल हैं। शुक्ला बताते हैं कि उनके बाग में भारतीय और विदेशी दोनों तरह की किस्में हैं। दक्षिण अफ़्रीका का सेंसेशन, अमेरिका का टॉमी एटकिंस और भारत में विकसित अरुणिका व प्रतिभा जैसी किस्में यहाँ एक साथ देखी जा सकती हैं। उनका दावा है कि कई किस्मों की शेल्फ लाइफ बेहतर है और कुछ किस्में निर्यात के लिहाज से भी उपयुक्त हैं।

एक ही पेड़ पर कई तरह के आम

इस बाग की एक और खासियत ग्राफ़्टिंग तकनीक है। कई पेड़ों पर अलग-अलग किस्मों की शाखाएं जोड़ी गई हैं, जिससे एक ही पेड़ पर कई प्रकार के आम लगते हैं। शुक्ला के अनुसार यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके लिए अनुभव और नियमित देखभाल की जरूरत होती है।

जब एक बड़े पेड़ की जगह लगाए गए 20 पेड़

शुक्ला बताते हैं कि उनके पास पहले दशहरी का पारंपरिक बाग था। लेकिन बदलते मौसम और उत्पादन की चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने बाग का स्वरूप बदलना शुरू किया। अब जहाँ पहले एक बड़ा पेड़ होता था, वहाँ लगभग 20 छोटे पौधे लगाए गए हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक आम के पेड़ों में एक साल अधिक और अगले साल कम फल आने की समस्या रहती है, जबकि नई किस्मों

और घने रोपण (हाई-डेंसिटी प्लांटेशन) से उत्पादन को अधिक नियमित बनाया जा सकता है।

सालभर फल देने वाली किस्में

शुक्ला का दावा है कि उनके पास 27 ऐसी किस्में हैं जो साल के बारहों महीने किसी न किसी अवस्था में फल देती रहती हैं। इन पेड़ों पर एक साथ फूल, कच्चे फल और पके फल देखे जा सकते हैं। उनका कहना है कि इन किस्मों में अल्टरनेट बियरिंग की समस्या भी कम है, यानी हर साल फल आने की संभावना बनी रहती है।

रासायनिक दवाओं से दूरी

बाग के प्रबंधन में गोबर की खाद, नीम की खली, नीम का तेल, दशपर्णी और अन्य जैविक उपायों का उपयोग किया जाता है। शुक्ला के अनुसार कीट प्रबंधन के लिए भी रासायनिक दवाओं पर निर्भरता कम रखी जाती है। उनका कहना है कि इससे फलों की गुणवत्ता और स्वाद पर सकारात्मक असर पड़ता है।

ग्लोबल वार्मिंग और दशहरी की चुनौती

शुक्ला का मानना है कि बढ़ते तापमान का असर कुछ पारंपरिक आम की किस्मों पर दिखाई देने लगा है। उनके अनुसार अत्यधिक गर्मी के दौरान फलों के अंदर गलन जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। इसी वजह से उन्होंने बाग में नई और विविध किस्मों को शामिल करने पर जोर दिया है।

100 रुपये का एक आम

बाग में मौजूद कुछ विदेशी किस्मों के आम आकार और बाजार मूल्य दोनों के कारण अलग पहचान रखते हैं। शुक्ला के अनुसार कुछ आम प्रति पीस बेचे जाते हैं और उनकी कीमत 100 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। वहीं कुछ किस्मों का बाजार मूल्य 400 रुपये प्रति किलो तक पहुँच जाता है।

किसानों के लिए क्या सीख?

शुक्ला का कहना है कि आम के बाग में सबसे जरूरी है पर्याप्त धूप, हवा, संतुलित सिंचाई और जैविक खाद का उपयोग। उनका मानना है कि नीम की खली और गोबर की खाद बाग के लिए सबसे उपयोगी हैं। साथ ही पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखने और शाखाओं को सहारा देने जैसी छोटी बातें भी उत्पादन पर बड़ा असर डालती हैं। लखनऊ का यह बाग केवल आम उत्पादन की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि एक किसान का जुनून, प्रयोग और वर्षों का अनुभव किस तरह एक साधारण बाग को सैकड़ों किस्मों के जीवित संग्रहालय में बदल सकता है।

'मैं मरी नहीं हूं...', 35 साल की इस हसीना के अंतिम संस्कार के कार्ड हुए वायरल, फिर खुद दिया फिटनेस का सबूत

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री और टीवी होस्ट ज्वेल मैरी इस समय काफी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर फैल रही है। हाल ही में इंटरनेट पर अफवाह है कि वह कैंसर का शिकार हो गई थी और अब उनका निधन हो गया है। उनके अंतिम संस्कार का निमंत्रण पत्र भी वायरल हो रहा है। यह अफवाह इतनी तेजी से फैलने लगी की अभिनेत्री को खुद सामने आकर इस पर अपनी सफाई देनी पड़ी।

ज्वेल मैरी की मौत की खबर हुई वायरल

ज्वेल मैरी ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि अब वह जिंदा है और एक ठीक-ठाक जिंदगी जी रही है। उन्होंने लोगों से इस बात की भी अपील की है कि वह किसी भी पुष्टि के बिना बेमतलब की अफवाहों पर ध्यान ना दें। वीडियो में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने तो उन्हें सोशल मीडिया पर मर ही दिया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी।

एक्ट्रेस ने दिया फिटनेस का सबूत

ज्वेल मैरी ने इस दौरान बताया कि

उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी आवाज खो दी और वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी फिटनेस का भी सबूत देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दिया। वीडियो में वह ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते हुए नजर आई।

ज्वेल मैरी ने वर्कआउट का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि "मैं मरी नहीं हूं। कुछ दिनों से लोग मुझे करने पर तुले हुए हैं और कुछ नहीं तो मुझे मार ही डाला है। लेकिन अब मेरे अंतिम संस्कार के कार्ड भी छाप दिए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। मैं अपनी मौत की सेज पर हूं और हिल भी नहीं सकती हूं।"

अभिनेत्री ने मलयालम भाषा में वीडियो में कहा कि "मैं यह वीडियो इसीलिए सजा कर रही हूं कि लोगों को पता चले कि 2 दिन पहले आई अफवाह झूठी है। दोस्तों मैं मरी नहीं हूं। 2023 में भी जो मैंने बातें कही थी उनको भी तोड़ मरोड़ कर फैलाया गया और गुमराह करने वाले लोग कैप्शन का इस्तेमाल करते हुए जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं मर चुकी हूं। इसीलिए मैं उन लोगों को बता देता हूं कि अभी मेरे अंतिम संस्कार की चाय पर उसे जाने की तैयारी करना पूरी तरीके से बेकार है।"

जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह अफवाह अभिनेत्री के साल 2023 में दिए गए एक पुराने बयान से

2023 में एक्ट्रेस ने की थी कैंसर पर बात

फैली है। तब उन्होंने एक इवेंट में कैंसर से अपनी लड़ाई को लेकर बात की थी। उन्होंने 2023 में केरल कैन नाम के एक इवेंट में अपनी कैंसर की लड़ाई के बारे में बताया था। इस इवेंट में बताई हुई बातों को कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने के लिए इस्तेमाल किया।

जब पहली बार कैंसर के बारे में चला था पता

ज्वेल मैरी ने 2023 में कैंसर को लेकर जब बताया था तो कहा था कि "मैं अपने रुटीन चेकअप के लिए एक बार हॉस्पिटल गई और मुझे खांसते वक्त काफी कफ निकल रहा था। डॉक्टर ने स्कैन करने की सलाह दिया और जब रिपोर्ट आई तो कुछ भी ठीक नहीं था। फिर डॉक्टर ने बायोप्सी करने के लिए कहा और इस पर सीधा इशारे यही था कि कैंसर हो सकता है और जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मैं खतरे में हूं।"

ज्वेल मैरी के करियर के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है और सुपरस्टार ममूटी के साथ में कई बेहतरीन फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। हालांकि इस विवाद पर उन्होंने यह तो साफ कर दिया है कि वह पूरी तरीके से ठीक है और उनके निधन की खबर झूठी है।

शरवरी और वेदांग के 'मस्कारा' ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, इतने करोड़ व्यूज के साथ बना वायरल सेंसेशन

(जीएनएस)।

इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा का रोमांटिक ट्रैक मस्कारा दर्शकों के दिलों को छूने में कामयाब रहा है और देखते ही देखते साल के सबसे चर्चित गानों में शामिल हो गया है।

1 करोड़ से अधिक व्यूज और सोशल मीडिया पर 1 लाख से ज्यादा रील्स के साथ मस्कारा इस साल का एक बड़ा वायरल म्यूजिक मोमेंट बनकर उभरा है। फिल्म के एक गीत से आगे बढ़कर यह अब एक डिजिटल फेनोमेनन का रूप ले चुका है। शर्वरी और वेदांग रैना की शानदार केमिस्ट्री से सजा मस्कारा, जिसे महान संगीतकार ए. आर. रहमान ने संगीतबद्ध किया है और जिसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं, दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इसकी चुलबुली रोमांटिक भावना, खूबसूरत विजुअल्स और तुरंत जुबान पर चढ़ जाने वाली धुन ने इसे हर प्लेटफॉर्म पर पसंदीदा बना दिया है। गाने ने फैन वीडियोज, डांस ट्रेंड्स और कंटेंट क्रिएटर्स के जरिए सोशल मीडिया पर एक बड़ी लहर पैदा कर दी है, जिससे यह एक सांस्कृतिक ट्रेंड बन गया है।

इस सफलता पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए शर्वरी ने कहा,"मैं हमेशा से बॉलीवुड संगीत की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूं क्योंकि गानों में लोगों की यादों और उनके खास पलों का हिस्सा बनने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए जिन गानों से मैं जुड़ी हूं, उन्हें दर्शकों से इतना प्यार मिलता देखना मेरे लिए बेहद खास है। तरस, हाँ के हाँ और अब मस्कारा - ये तीनों गाने अपने मूड और व्यक्तित्व में पूरी तरह अलग हैं, लेकिन दर्शकों का प्यार इन सभी को समान रूप से मिला है।

मस्कारा को लेकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों ने इसे अपनी रचनात्मकता के साथ अपनाया है। हर दिन मुझे इस गाने के

नए-नए और अनोखे संस्करण देखने को मिलते हैं। अलग-अलग तरीकों से लोगों का इस गाने से जुड़ना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। एक कलाकार के तौर पर इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं कि दर्शक आपके काम को अपने जीवन और अपनी कहानियों का हिस्सा बना लें। लोगों द्वारा बनाए जा रहे सभी वर्जन मुझे बेहद पसंद आ रहे हैं और उम्मीद है कि वे इस गाने के साथ इसी तरह मस्ती करते रहेंगे।"

इस वायरल सफलता के केंद्र में शर्वरी हैं, जिनका पगड़ी वाला लुक और सहज आकर्षण गाने की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बातों में से एक बन गया है। फैन एडिट्स से लेकर रील्स तक, दर्शक शर्वरी के मस्कारा अवतार को खूब पसंद कर रहे हैं, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता का एक और प्रमाण है।

गाने की जबरदस्त लोकप्रियता ने मैं वापस आऊंगा को लेकर उत्साह और भी बढ़ा दिया है। इम्तियाज अली की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शर्वरी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। भारत के विभाजन की भावनात्मक पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म ने अपनी घोषणा के बाद से ही दर्शकों के बीच खास उत्सुकता पैदा कर रखी है। 12 जून को रिलीज होने जा रही मैं वापस आऊंगा अब क्टकु की 2026 की मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन फिल्म्स की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गई है। यह फिल्म को लेकर दर्शकों के बढ़ते उत्साह और देशभर में इसके प्रति बढ़ती जिज्ञासा को दशार्ता है।

फरहान अख्तर के साथ डॉन 3 वाले विवाद के बाद एफडब्लूआईसीई द्वारा धुरंधर एक्टर को लगाया गया बैन हट गया

फरहान अख्तर के साथ डॉन 3 वाले विवाद के बाद FWICE ने धुरंधर एक्टर को बैन कर दिया था। लेकिन अब वो बैन हट गया है। बता दें कि रणवीर सिंह ने इस बैन के खिलाफ एक्शन लेने का मन बनाया था और वो खुद भी इस मामले को लेकर अदालत पहुंचे थे। रणवीर ने संगठन को कानूनी नोटिस भेजा जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है।

FWICE आज यानि 3 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कई बातें इसमें रखी थी। उन्होंने बताया कि अभिनेता के द्वारा नोटिस भेजा गया है और बातों को स्पष्ट रूप से रखने की बात की गई है।

हट गया प्रतिबंध, नोट जारी

रणवीर सिंह पर प्रतिबंध हटाते हुए अशोक पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

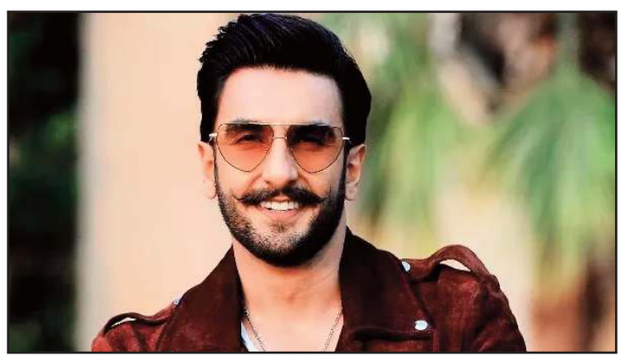

उन्होंने मीडिया से कहा कि, संस्था ने रणवीर से संपर्क करने की बार-बार कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उनपर बैन लगाया था। लेकिन अब एक FWICE ने एक नोटिस जारी करते हुए खुले शब्दों में कहा है कि रणवीर सिंह पर बैन हटाया जा रहा है। अदालत का दरवाजा खटखटाते ही ये फैसला सामने आया है और लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं। धुरंधर और धुरंधर 2 की सफलता के बाद इस तरह की खबरों का आना काफी हैरान करने वाला था।

लोग कर रहे हैं कमेंट्स

इस खबर के सामने आने के बाद रणवीर सिंह के फैंस लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "यह देखकर अच्छा लगा कि एफडब्ल्यूआईसीई ने रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का निर्देश वापस ले लिया है।" एक ने लिखा, "बस हवा निकल गई।" एक ने लिखा, "सरकार पक्ष में है रणवीर के।" एक ने लिखा, "धुरंधर।" एक ने लिखा, "क्या हुआ, करवा ली बेज्जती।" इस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं।

पत्नी ऋचा चड्ढा को लेकर अली फजल का बड़ा खुलासा

(जीएनएस)।

अपने दमदार और अलग-अलग तरह के किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता अली फजल ने हाल ही में अपनी पत्नी और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के साथ अपने रचनात्मक रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि दोनों को ऐसी कहानियां और किरदार चुनना पसंद है जो दर्शकों के दिलों में लंबे समय तक अपनी जगह बना सकें।

अली और ऋचा दोनों ने अपने-अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया। ऋचा का फुकरे फ्रेंचाइजी में निभाया गया भोली पंजाबन का किरदार हो या मिर्जापुर में अली का गुड्डू पंडित, दोनों ही कलाकार हमेशा ऐसे किरदारों की ओर आकर्षित हुए हैं जो अलग पहचान बनाते हैं।

इस बारे में बात करते हुए अली

फजल ने कहा, "ऋचा और मैं हमेशा से ऐसे कलाकार रहे हैं जो सबसे पहले अच्छे किरदारों की तलाश करते हैं। हमारे लिए कभी किसी खास इमेज में फिट होना या पारंपरिक रास्तों पर चलना महत्वपूर्ण नहीं रहा। हम हमेशा ऐसे किरदारों की तलाश में रहे हैं जो हमें चुनौती दें और दर्शकों के दिलों में बस जाएं। मुझे लगता है कि इस मामले में हम दोनों खुद को काफी खुशकिस्मत मानते हैं।"

अली आगे कहते हैं, "जब आप फुकरे की भोली पंजाबन या मिर्जापुर के गुड्डू पंडित जैसे किरदारों को देखते हैं, तो महसूस होता है कि ये सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। एक अभिनेता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि दर्शकों ने आपके किरदार को इतनी गहराई से अपनाया हो।"

वह आगे कहते हैं, "हम दोनों अपने काम और चुनावों को लेकर एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। हम इस पेशे की प्रक्रिया और इसकी अनिश्चितताओं का सम्मान करते हैं।

हर बड़ी जीत से पहले कुशीनगर, क्या 2027 की पटकथा भी यहीं से लिखेगी भाजपा, जानिए यह जिला क्यों है खास

कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। यह जिला पार्टी के लिए पूर्वांचल की चुनावी रणनीति का एक अहम केंद्र बन चुका है।

(जीएनएस)।

कुशीनगरः भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कुशीनगर का महत्व सिर्फ एक जिले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूर्वांचल की चुनावी रणनीति का अहम केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया कुशीनगर दौरा और उनके भाषण का राजनीतिक स्वर यह संकेत देता है कि बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद शुरू कर दिया है।

तमकुहीराज में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ-साथ कानून-व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई, गन्ना किसानों के भुगतान, मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

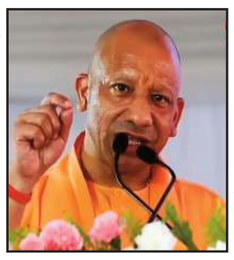

जानिए बीजेपी के लिए कुशीनगर क्यों है खास

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि पूर्वांचल के मतदाताओं को साधने की रणनीतिक कोशिश भी थी। दरअसल, कुशीनगर का बीजेपी से विशेष राजनीतिक जुड़ाव रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की पूर्वांचल की पहली बड़ी रैली पडरौना में हुई थी। 2019 में पीएम मोदी ने कप्तानगंज से चुनावी अभियान को धार दी।

2022 चुनाव से पहले एयरपोर्ट का हुआ लोकार्पण

2017 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की पूर्वांचल की पहली रैली फाजिलनगर में हुई, जबकि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लोकार्पण के साथ पीएम मोदी और योगी की संयुक्त रैली ने चुनावी माहौल बनाया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी अमित शाह और राजनाथ सिंह की पूर्वांचल की शुरूआती सभाएं कुशीनगर में ही हुईं।

पूर्वांचल साधने की रणनीति का केंद्र

राजनीतिक दृष्टि से कुशीनगर पूर्वांचल, बिहार सीमा और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि बीजेपी हर बड़े चुनाव से पहले यहां से संदेश देने की कोशिश करती है। योगी आदित्यनाथ के ताजा दौरे को भी पार्टी की उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए विकास और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर जनता के बीच भरोसा मजबूत करने के साथ 2027 के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है।

क्या फिर भाग्यशाली साबित होगा कुशीनगर

पिछले एक दशक में बीजेपी ने जिन चुनावों में कुशीनगर से अभियान शुरू किया, उनमें उसे बड़ी सफलता मिली। ऐसे में अब राजनीतिक नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 2027 के चुनाव में भी कुशीनगर बीजेपी के लिए वही राजनीतिक संजीवनी साबित होगा, जिसने पहले कई चुनावी जीत की पटकथा लिखी है।

यूपी सरकार ने बदला मंत्रियों का जिला प्रभार; सीएम योगी समेत सभी मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारी

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रभारी मंत्री अपने आवंटित जिलों में नियमित दौरे करेंगे.

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के जिला प्रभार में फेरबदल करते हुए नई सूची जारी कर दी है. मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर बुधवार को जारी आदेश के अनुसार अब सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री को एक या दो जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार का उद्देश्य इन जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन, शिकायत निवारण और विकास कार्यों की सीधी निगरानी सुनिश्चित करना है.

मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को कई विभागों का दायित्वः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबंधन, सामान्य प्रशासन, सूचना, नियोजन, लोक सेवा प्रबंधन, न्याय, धार्मिक कार्य, लोक निर्माण समेत 20 से अधिक विभागों का प्रभार पहले से ही है.

नई व्यवस्था में उन्होंने किसी एक जिले का प्रभार नहीं लिया है, लेकिन समन्वय की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी. उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास, समग्र ग्रामीण विकास, ग्रामीण अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर और सार्वजनिक उद्यम विभाग मिले हैं, उन्हें प्रतापगढ़ जिले का प्रभार दिया गया है. वहीं, दूसरे उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभागों की जिम्मेदारी है. उनको अभी किसी जिले की जिम्मेदारी नहीं दी गई.

कैबिनेट मंत्रियों को मिली जिलेवार जिम्मेदारीः कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या और बस्ती जिले का प्रभार मिला है. जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज और गोरखपुर देखेंगे.

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वाराणसी और लखनऊ के प्रभारी बनाए गए हैं. महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य को इटावा और हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है. गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी अलीगढ़ और फिरोजाबाद देखेंगे.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को झांसी और फरुर्खाबाद का प्रभार सौंपा गया है. औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन और निवेश मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मिजार्पुर और चित्रकूट के प्रभारी होंगे. श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर देखेंगे. नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को जौनपुर और भदोही की जिम्मेदारी मिली है.

राज्य मंत्रियों को भी बंटे जिलेः राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में असीम अरुण को हरदोई और मेरठ, जेपीएस राठौर को संभल और बरेली, दयाशंकर सिंह को देवरिया और मऊ का प्रभार दिया गया है. आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल लखीमपुर खीरी, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल बिजनौर, स्टांप एवं न्यायालय शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल गाजीपुर के प्रभारी होंगे.

राज्य मंत्रियों में मयंकेश्वर शरण सिंह प्रतापगढ़, दिनेश खटीक शामली, संजीव गोंड चंदौली, बलदेव सिंह ओलख पीलीभीत, जसवंत सिंह सैनी बागपत, रामकेश निषाद हमीरपुर, मनोहर लाल मनु कोरी महोबा, संजय सिंह गंगवार जालौन, बृजेश सिंह गौतमबुद्ध नगर के प्रभारी बनाए गए हैं.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रभारी मंत्री अपने आवंटित जिलों में नियमित दौरे करेंगे, जनसुनवाई करेंगे और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे.

लखनऊः केजीएमयू में 10 लाख का बिल अचानक पहुंचा 45 लाख! यूरोलॉजी विभाग प्रमुख की छुट्टी, तीन नौकरी से बर्खास्त

(जीएनएस)।

लखनऊ के केजीएमयू में 'असाध्य योजना' के तहत करोड़ों के दवा घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है. कागजों पर मरीजों को फर्जी भर्ती दिखाकर 10 लाख का बिल 45 लाख पहुंचाया गया. पांच सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद वाइस चांसलर ने यूरोलॉजी हेड डॉ. अपुल गोयल को हटाकर चार कर्मचारियों को सस्पेंड व बर्खास्त किया है.

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में असाध्य योजना के तहत करोड़ों रुपये के दवा खरीद घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है. केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग के हेड डॉ. अपुल गोयल को उनके पद से हटा दिया गया है. इसके साथ ही एक रेगुलर फार्मासिस्ट को सस्पेंड और आउटसोर्सिंग के 3 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आपराधिक मामला चलाने की मांग की है. साथ ही, रकम को आउटसोर्सिंग एजेंसी से वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

केजीएमयू के अधिकारियों के मुताबिक, यूरोलॉजी विभाग में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए चलाई जा रही असाध्य योजना के तहत हर महीने करीब 10 लाख रुपये की दवाएं खरीदी जाती थीं. लेकिन इस साल की शुरूआत में अचानक दवाओं का खर्च सामान्य से 3 से 4 गुना बढ़ गया. पिछले महीने तो हद ही हो गई, जब दवा खरीद का बिल अचानक 45 लाख रुपये पहुंच गया. इतनी बड़ी रकम देखकर प्रशासन के कान खड़े हो गए. जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो चौंकाने वाला सच सामने आया. लगभग 40 मरीजों के नाम पर कैंसर की महंगी दवाएं, प्रोटीन और आयरन सप्लीमेंट्स बार-बार खरीदे दिखाए गए थे.

जांच में पता चला कि कागजों पर इन मरीजों को कई-कई बार भर्ती दिखाकर सरकारी फंड का अंधाधुंध दुरुपयोग किया जा रहा था. दवा खरीद में इस बड़ी हेराफेरी के सामने आने के बाद केजीएमयू की वाइस चांसलर डॉ. सोनिया नित्यानंद ने तुरंत एक्शन लिया. उन्होंने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया. कमेटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद केजीएमयू में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई.

केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि यूरोलॉजी विभाग के हेड डॉ. अपुल गोयल को योजना की निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रशासनिक पद से हटा दिया गया है. निष्पक्ष जांच पूरी होने तक वह इस पद से दूर रहेंगे. उनकी जगह जनरल सर्जरी विभाग के डॉ. एचएस पाहवा को यूरोलॉजी विभाग का कार्यवाहक हेड नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, घोटाले में सीधे तौर पर शामिल आउटसोर्सिंग कर्मचारी पी. सिंह, एच. श्रीवास्तव और एस. तिवारी की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं. वहीं यूरोलॉजी विभाग के लोकल परचेज काउंटर पर तैनात रेगुलर फार्मासिस्ट अरशद वासी को सस्पेंड कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि पुलिस जांच के बाद इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

लखनऊ स्टेशन पर नहीं रुकेंगी ये गाड़ियां, कई ट्रेनें बदले हुए रूट से चलेंगी

(जीएनएस)।

लखनऊ, चारबाग स्टेशन पर कॉनकोर्स कार्य के कारण पावर ब्लॉक लिया गया है। इसके लिए कई ट्रेनों को ठहराव नहीं मिल सकेगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मार्ग परिवर्तन की जानकारी दी है।

पूर्वोत्तर रेलवे ने लखनऊ स्टेशन पर चल रहे कॉनकोर्स कार्य के कारण कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव चार जून तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है क्योंकि इन ट्रेनों को लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं मिलेगा।

उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए की ओर से कॉनकोर्स कार्य किया जा रहा है। इसके चलते यातायात और पावर ब्लॉक लिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मार्ग परिवर्तन की जानकारी दी है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वह यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें।

टनकपुर से चलने वाली 15074 टनकपुर-सिंगरौली एक्सप्रेस तीन जून को आलमनगर-ट्रांसपोर्ट नगर-उतरेटिया के रास्ते चलेगी। इसी तरह 15076 टनकपुर-शक्तिनगर एक्सप्रेस चार जून को इसी मार्ग से गुजरेगी। शक्तिनगर-टनकपुर एक्सप्रेस (15075) तीन जून को उतरेटिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमनगर के रास्ते चलेगी। बनारस-देहरादून एक्सप्रेस (15119) चार जून तक इसी परिवर्तित मार्ग का उपयोग करेगी। इन सभी ट्रेनों का लखनऊ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। हालांकि, इन्हें परिवर्तित मार्ग पर आलमनगर और उतरेटिया स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव मिलेगा।

पावर ब्लॉक से गोरखपुर से चलने वाली कुछ ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। मार्ग परिवर्तित होने के कारण लखनऊ स्टेशन पर किसी भी प्रभावित ट्रेन का ठहराव नहीं होगा। गोरखपुर से चलने वाली ट्रेनों को बादशाह नगर और ऐशबाग स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव मिलेगा। डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस के लिए बाराबंकी, लखनऊ, बालामऊ और हरदोई स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा। इस ट्रेन को बुढ़वल और सीतापुर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा।

गोरखपुर और अन्य क्षेत्रों से प्रभावित ट्रेनें

गोरखपुर से चलने वाली 12571 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस तीन जून को बाराबंकी-मल्हौर-ऐशबाग-कानपुर सेंट्रल के रास्ते जाएगी। 12555 गोरखपुर-बठिंडा एक्सप्रेस भी चार जून तक इसी मार्ग से चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल-नाहरलागुन एक्सप्रेस (22412) चार जून को मानक नगर-ऐशबाग-मल्हौर के रास्ते परिवर्तित होगी। पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस (15066) और ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस (11123) भी तीन और चार जून को इसी मार्ग से चलेंगी। डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस (15909) तीन जून को बुढ़वल-सीतापुर-शाहजहांपुर के रास्ते चलाई जाएगी।

गोरखपुर में सीएम योगी बोले- 'देश में यूपी सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य'

संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2026 के शुभारंभ के लिये बुधवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया.

(जीएनएस)।

गोरखपुर : गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2026 के शुभारंभ के लिये बुधवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को संबोधित किया. इस मौके पर गोरखपुर मंडल के चार जिलों के अग्रणी किसान, अधिकारी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी शामिल रहे.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तो देश के भीतर क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है, फिर भी हम चीनी, एथेनॉल, आलू, दूध, सब्जी के उत्पादन में पहले नंबर पर हैं. उन्होंने कहा कि यह सब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी के किसान हित और कल्याण को लेकर बनाई गई योजनाओं का परिणाम है.

उन्होंने कहा कि किसान से बड़ा वैज्ञानिक कौन है. किसान जानता है कि कब कौन सी फसल पैदा करनी है? उत्तर प्रदेश जैसा राज्य सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखता है. सिंचाई के साधन भी यहां उपलब्ध हैं. लंबित परियोजनाओं को पूरा किया गया है. जिसमें बाणसागर परियोजना, सरयू नहर परियोजना और बुंदेलखंड की परियोजनाएं शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था से आच्छादित किया गया है. यही नहीं सरकारी नलकूप के साथ निजी नलकूप को भी फ्री बिजली प्रदेश सरकार दे रही है, जिस पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च आ रहा है.

सीएम ने कहा कि उन्हें किसानों की मेहनत पर फक्र होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से इसे बीमारू प्रदेश से बाहर निकलते हुए 8 से 18 फीसदी कृषि विकास डर तक पहुंचाने का कार्य किया है. आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश का राज्य है.

उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की भी चिंता साफ दिखाई देती है. इसलिए उन्होंने किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसानों को मजबूती दी है. आप किसानों को अपनी जरूरत के लिए साहूकारों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जब प्रदेश में उनके नेतृत्व में सरकार गठित हुई थी तो उन्होंने भी अन्नदाता किसान के लिए अपनी पहली कैबिनेट में फसल ऋण को लेकर बड़ी योजना की सौगात दी थी.

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के किसानों को अगर अपनी फसलों की मुंह मांगी कीमत चाहिए तो उसे एक्सपोर्ट के लायक तैयार करें. यूरोप के बाजार इसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं.

उन्होंने औद्यानिक फसलों की चर्चा करते हुए कहा कि अगर आप अच्छी किस्म का आम पैदा करते हैं तो जो आम अपने देश में ₹40 प्रति किलो की कीमत पर होगा, वह विदेश जाकर ₹800 तक की कीमत हासिल करेगा.

उन्होंने कहा कि इस निर्यात में कार्गो की कीमत को भी अगर जोड़ लिया जाएगा तो अधिकतम डेढ़ सौ रुपये ही आएगा. ऐसे में किसानों को बड़ा फायदा एक्सपोर्ट वाली फसलों पर होने वाला है. जिसमें वह औद्यानिक फसलों के साथ सब्जियों के उत्पादन में भी हाथ आजमा सकते हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों को उन्नत तकनीक और सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है. यही वजह है कि सरकार के साथ किसानों ने मेहनत करना प्रारंभ किया है तो आज परिणाम भी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सामने भी नजर आ रहा है.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से 2014 का कालखंड किसानों की आत्महत्या का दौर था. जिसके पीछे अच्छे बीज का अभाव, लागत का बढ़ना, एमएसपी का सही न होना और आपदा जैसी स्थिति में रहता का न मिलाना था. सीएम ने किसानों से अपील किया कि वह दलहन, तिलहन के पैदावार पर भी जोर दें जिससे इसके आयात पर देश को अधिक धन खर्च न करना पड़े.

इस रबी गोष्ठी को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि विज्ञान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वह किसान ही हैं. जिनके प्रयासों से देश समृद्ध होता है. उन्होंने कहा कि दलहन, तिलहन की बात को अगर छोड़ दें तो खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं.

सीएम ने प्रमाण पत्र दिये

गोरखपुर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास : गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ऋक्रऊअ) क्षेत्र में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स एवं एहर, छक्क्ष् आवासीय परिसर सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया. इस अवसर पर करीब 208 करोड़ रुपये के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है. इस नीति से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति न मानने वाले जिस बोली-भाषा में समझेंगे, उसी में समझा दिया जाएगा. विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सर्वाधिक जरूरी है. सुरक्षा के बिना न सुशासन आ सकता और न ही समृद्धि आ सकती है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस व एलआईजी भवन के आवंटियों को प्रमाण पत्र वितरित किए. इस अवसर पर औद्योगिक भूमि के आवंटियों को भी मुख्यमंत्री के हाथों आवंटन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ. सीएम ने प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से यूपी ने सुरक्षा का एक मॉडल उपलब्ध कराया है. सुरक्षा के इस मॉडल से औद्योगिक विकास हुआ और लाखों नौजवानों को रोजगार मिला. अकेले गीडा में पिछले कुछ वर्षों में 50 हजार युवाओं को रोजगार मिला है. सुरक्षा का माहौल बने बिना यह संभव नहीं था.

सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि विकास की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी, सुरक्षा सबको मिलेगी और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सबको मिलेगा. उन्होंने कहा कि किसी ने मनबढ़ई करके गरीबों का हक छीनने की कोशिश की, व्यापारियों को धमकाने की कुत्सित प्रयास किया या बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो सरकार छोड़ेगी नहीं. ऐसे लोगों को पाताल से भी खोजकर निकाल लाएंगे. यूपी में जीरो टॉलरेंस के भाव से यही कार्य किया जा रहा है.

लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़क के किनारे मिले तीन सौ कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में सड़क के किनारे बिजली के वितरण में प्रयोग में लाए जाने वाले तीन सौ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सड़क के किनारे पड़े होने के खलबली मच गई। बुधवार को मिले इन बॉक्स से उपकरण और तांबा निकाला गया था। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता राम कुमार को इस प्रकरण की जानकारी ही नहीं है।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं को नो ट्रिपिंग बिजली देने के लिए लखनऊ में रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) यानी बिजली सुधार योजना के तहत एरियल बंच केबल एबीसी के साथ उपभोक्ताओं के घर के सामने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाए गए।

इन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए गए। राजधानी में यह अधिकांश जगह देखे जा सकते हैं, लेकिन अमौसी जोन के काकोरी व आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में पेटी ठेकेदार ने इनका प्रयोग काफी कम किया। काकोरी से आलमनगर के बीच पड़ने वाले शाहपुर भमरौली में बुधवार को सड़क के किनारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिले। यह

डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पेटी ठेकेदार ने गांवों में लगाने के बजाए, इनके भीतर के उपकरण और तांबा निकाला और सड़क के किनारे फेंक दिया।

बता दें कि सरकारी क्रय में एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कीमत ढाई हजार रुपये है। अगर यही बॉक्स एक फेज कनेक्शन का होता तो उसकी कीमत 950 रुपये तक हैं और थ्री फेस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की कीमत ढाई हजार है। एक बॉक्स से दस उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया जा सकता है। इन बॉक्स से कनेक्शन देने के बाद बिजली फेस में छेड़छाड़ की संभावना नहीं रहती, कनेक्शन देने के बाद यह बॉक्स संबंधित लाइन मैन बंद कर देता है।

अमौसी जोन के एफसीआइ बिजली उपकेंद्र के अंतर्गत स्थित शाहपुर भमरौली में सड़क किनारे तीन सौ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिलने से मीटर सेक्शन के अभियंताओं को चिंता सता रही है कि आखिर एजेंसी ने ऐसा क्यों किया। अभियंताओं को सुपरविजन की जिम्मेदारी थी। मौके पर पहुंचे बिजली कर्मियों ने जांच के दौरान पाया कि बॉक्स के अंदर से सारे उपकरण गायब थे। सिर्फ डिब्बे मौके पर पाए गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस पेटी ठेकेदार ने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रखने के लिए मकान किराए पर लिया था, वह काफी दिनों से किराया नहीं दे रहा था और भवन स्वामी दबाव बना रहा था। पेटी ठेकेदार रातों-रात मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की संपत्ति डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को शाहपुर भमरौली में सड़क किनारे फेंककर गायब हो गया।

मामला संज्ञान में नहीं

मुख्य अभियंता, अमौसी जोन राम कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा है तो गंभीर विषय है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिस एजेंसी के जिम्मे डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स लगाने का काम था और जिस अभियंता को पूरा सुपरविजन करना था, उनकी जवाबदेही तय होगी। दोषी मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ में वीडियोग्राफर के साथी ने ही रची थी लूट की साजिश, तीन गिरफ्तार

(जीएनएस)।

लखनऊ। माल के रानीखेड़ा निवासी वीडियोग्राफर अशोक यादव से लूट की साजिश चार वर्षों से उसके साथ काम करने वाले रोहन ने अपने साथियों के साथ रची थी। बुधवार को पुलिस ने रोहन समेत घटना में शामिल उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से लूट का सामान भी बरामद हुआ है।

पीड़ित अशोक यादव ने तहरीर में बताया कि रविवार रात आशू नाम के युवक ने वाट्सएप के जरिए जन्मदिन कार्यक्रम के लिए बुकिंग कर उन्हें बुलाया था। वह साथी शनी, शशांक गुप्ता, सचिन गौतम और रोहन कुमार के साथ कार से इटौंजा के हीरापुरवा तिराहे के पास पहुंचे तभी दो बाइक पर सवार चार युवक आए और असलहे के बल पर धमकाते हुए कैमरा, लेंस समेत 15 लाख रुपये का सामान लूट ले गए।

पीड़ित ने इटौंजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया और साथी रोहन पर भी घटना में शामिल होने का शक जताया था। बुधवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घटना का राजफाश करते हुए रोहन समेत दो अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इटौंजा थाना

प्रभारी सोबरन सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को इटौंजा चौराहे के पास रोका गया।

इसकी पहचान देवरिया के भलुवनी निवासी विपिन मिश्रा उर्फ दुर्लभ के रूप में हुई। तलाश में इसके पास से तमंचा, मोबाइल फोन और दो कारतूस मिली। पूछताछ में उसने बताया कि वीडियोग्राफर से लूट के मामले में बुकिंग करने के लिए इसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। घटना के बाद इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड फेंक दिया था।

पूछताछ में उसने बिहार के सिवान निवासी रोहन कुमार और गोंडा के इटियाथोक निवासी राम अनुज के रूप में हुई। रोहन वर्तमान में तालकटोरा के गढ़ी कनौरा में रहता था। विपिन की निशानदेही पर अन्य दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तीनों ने लूट की बात स्वीकार की और रोहन ने बताया कि पूरी घटना की साजिश उसी ने रची थी। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। अन्य फरार आरोपितों की तलाश जारी है।